Irregularities in State Bank of Indore

2011. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the branchwise details of irregularities, misappropriation, fraud cases detected/reported in the State Bank of Indore from April, 1991 upto June, 1992;

(b) what is the amount involved in each case;

(c) what is the number of officials found guilty and the action taken by the Bank Management; and

(d) what steps have been taken, or are being taken to recover the amount involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House

Outstanding Agricultural Loan

2012. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of agricultural loans that are overdue in nationalised banks;

(b) what is the total amount involved;

(c) what is the date from which they are overdue; and

(d) what are the bankwise details of principal as well as accrued interest component of these loans as on the 31st March, 1992?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) The number of agricultural loan accounts that are overdue in 20 nationalised banks and the total amount involved therein as at the end of March, 1991 (latest available) was 5496987 and Rs. 2298.94 crores respectively.

(c) and (d) The data reporting system of Reserve Bank of India does not generate the date from which the loan accounts are overdue. Similarly, no separate information is collected on the break-up of the overdues outstanding against principal and interest.

Liberalisation of FERA

2013. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under its consideration to substantially liberalise the Foreign Exchange Regulation Act;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) by when these proposals will be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Review of Foreign Exchange Regulation Act, 1973 is under the consideration of the Government. While it is premature to divulge any details at this stage, a Bill on the subject will be introduced in the Parliament at the appropriate time.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर, जनकपुरी, नई दिल्ली के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2014. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर की जनकपुरी, नई दिल्ली शाखा के अधिकारियों ने मार्च-जुलाई 1991 की अवधि के दौरान लगभग 35 लाख रुपए की जमा धन राशियां बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई थीं ;

(ख) यदि हां तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवासों के लिए दिए गए ऋण

2015. **डा० बापू कालदाते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास सुविधा के लिए कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने लोगों को कितनी-कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है ; और

(ग) ऋण दिए जाने के निबंधन और शर्तें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक अलग-अलग व्यक्तियों को सीधे ही आवास वित्त प्रदान नहीं करता है । राष्ट्रीय आवास बैंक अपने मार्गनिर्देशों के अनुसार संविस्तरित किए गए पात्र ऋणों के संबंध में सभी पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं (अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त संस्थायें और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां) को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है ।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक की विभिन्न पुनर्वित्त योजनाओं (राज्य स्तरीय विकास बैंकों द्वारा चलाए गए विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचर के लिए अंशदान सहित) के अंतर्गत 8.50 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए उसने जून, 1992 तक कुल 1198.09 करोड़ रुपए का संवितरण किया ।

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक नए आवास एककों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए आवास ऋणों के संबंध में 100% पुनर्वास प्रदान करता है :—(i) 40 वर्ग मी० से अनाधिक के निर्माण क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए तक (ii) 40 वर्ग मी० से अधिक के निर्मित क्षेत्र लेकिन 2 लाख रुपए से अनाधिक की लागत वाले एककों के लिए ऋण राशि तक और (iii) बड़ी मरम्मतों सहित उन्नयन के लिए 30,000 रुपए तक ,राष्ट्रीय आवास बैंक, आकार/लागत पैरामीटरों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, तैयार की गई उन समन्वित भूमि विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के लिए, जो (i) सार्वजनिक एजेंसियों, (ii) सहकारी समितियों, (iii) व्यावसायिक विकासकों द्वारा और (iv) नियोजकों द्वारा किराया आवास के लिए शुरू की जा सकती है, भी 100 पुनर्वित्त प्रदान करता है ।

RBI Inquiry into Inspection System through a Consultancy Firm

2016. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the RBI Governor ordered an inquiry into the inspection systems of the RBI by a Management and Consultancy firm;

(b) if so, what are the terms of reference, name of the firm and fees settled;

(c) whether the firm has submitted its report;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (e) The infromation is be ing collected and will be laid on t he Table of the House.